

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : ०५ अगस्त, 2006

विषय: मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल परिसर में स्थित ब्लाक-डी के वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत कार्यालय को मरम्मत एवं रंगाई-पुताई हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-545/UHC/Admn.B/Const./2005, दिनांक 4.3.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल परिसर में स्थित ब्लाक-डी के वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई हेतु ₹ 1,16,000/- की लागत के आगणन का टेंडर-एन्ड-सी-से परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 1,16,000/- (रुपये एक लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विस्तरेण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेंट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरोक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) कार्य कराने समय यह सुनिश्चित करने कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।
- (8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का कार्यकारी इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

- (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टार चर्चेंज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अभिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत संख्या-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-102-उच्च न्यायालय-03 उच्च न्यायालय-00-29-अनुक्षण" के नामे डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-489/XXVI(S)/2006, 21.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव ।

संख्या-19-चो।2/XXXVI(1)/2006-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इन्वेंटरी), ओवराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कौषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अभिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०अई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।

- (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपलब्धता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजन-102-उच्च न्यायालय-03 उच्च न्यायालय-00-29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-489/XXVI(5)/2006, 21.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव।

संख्या-19-च(2)/XXXVI(1)/2006-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महासेवाकार (लेखा एवं हकदारों), ओम्बराय विलिटिंग, उत्तरांचल, पञ्जरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन।
7. एन० एड्डी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव।